



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]
No. 43]गई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2003/चैत्र 10, 1925
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2003/CHAITRA 10, 1925

महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 26 मार्च, 2003

सं. टीएएमपी/7/2003-टीपीटी.—महापत्रन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण तांबे के संकेत्रण तथा कोयले पर परिमाण छूट योजना की समीक्षा संबंधी तृतीकोरिन पत्तन न्यास के प्रस्ताव को एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन करता है।

मामला सं. टीएएमपी/7/2003-टीपीटी

तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी)

आवेदक

आदेश

(मार्च, 2003 के 17वें दिन पारित)

यह मामला तृतीकोरिन पत्तन न्यास द्वारा तांबे के सान्द्र तथा कोयले से संबंधित 'परिमाण छूट योजना' की समीक्षा के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1 इस प्राधिकरण ने दिनांक 20 सितंबर, 2002 को टीपीटी के सामान्य पुनरीक्षण मामले पर एक आदेश पारित किया था। आदेश में वर्णित कारणों के द्वारा प्राधिकरण ने यह माना कि कॉपर कन्सन्ट्रेट की विशिष्ट प्रविष्टि के अस्तर्गत वर्गीकृत किया जाना उद्यित था इसलिए कॉपर कन्सन्ट्रेट जैसे विशिष्ट मद के घाट शुल्क दर में परिवर्तन नहीं किया गया। तथापि, कॉपर कन्सन्ट्रेट के व्यापार/यातोयात के परिमाण तथा लागत विवरण में दर्शायी गई बढ़ोतरी वाली/अतिरिक्त वित्तीय स्थिति के महेनजर प्राधिकरण ने वर्तमान स्तर पर आधार दर को ध्यान में रखकर इस मद के लिए 'परिमाण छूट योजना' निर्धारित की है। उसी प्रकार इस बात को ध्यान में रखकर कि टीपीटी में हेडल की जाने वाली वस्तुओं में कोयला प्रमुख है, आधार घाट शुल्क में कोई परिवर्तन किए बिना कोयले के लिए भी परिमाण छूट योजना शुरू की गई है।

2.2 धूकि एसपीआईसी ने जो टीपीटी के प्रमुख उपयोक्ताओं में है, ने समर्थन व्योरों के साथ कोई ठोस सुझाव प्रस्तुत नहीं किया था इसलिए टीपीटी तथा एसपीआईसी की परिमाण योजना को शुरू करने संबंधी मुद्दे की जाँच करने तथा सहमति वाला प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

3.1 मैसर्स स्टर्लिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एसआईएल) ने परिमाण छूट योजना के लागू होने की तिथि के बारे में यह जानना चाहा है कि क्या प्रतिवर्ष वाली तिथि का अर्थ पत्तन का वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च 2001) है, और यदि ऐसा है तो क्या परिमाण योजना चालू वित्तीय वर्ष में लागू होगी ?

3.2 इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जा चुका है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से लेकर परिमाण छूट योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि यानी 20 अक्टूबर, 2002 के बीच संचालित कॉपर कन्सन्ट्रेट के परिमाण पर संशोधन पूर्व के दरमान के अनुसार घाट प्रभार लगेगा, जहाँ तक वित्तीय वर्ष 2002-03 का प्रश्न है, तो केवल 'योजना' के कार्यान्वयन की तिथि से लेकर 31 मार्च, 2003 के बीच संचालित कॉपर कन्सन्ट्रेट का परिमाण घाटशुल्क दर में छूट योग्य होगा। यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से संचालित माल के परिमाण की गणना परिमाण छूट योजना के प्रभावी होने की तारीख से देय घाटशुल्क दर के उचित स्तर के निर्धारण हेतु की जाएगी।

3.3 हमारे स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में, टीपीटी ने यह उल्लेख किया है कि परिमाण छूट योजना पूर्ण रूप में केवल 19 अक्टूबर, 2002 से प्रभावी हो सकती है, तथा प्रतिवर्ष जैसे पारिभाषिक शब्द का अर्थ है उक्त आदेश के कार्यान्वयन की तारीख से चालू वर्ष। इस पृष्ठभूमि में इसने प्राधिकरण से दिए गए स्पष्टीकरण की समीक्षा तथा उसकी पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लंबित रखते हुए दिनांक 19 अक्टूबर, 2002 से प्रत्येक अनुगामी वर्ष के 18 अक्टूबर तक परिमाण छूट योजना के कार्यान्वयन के अनुमोदन का अनुरोध किया है।

4.1 इस प्राधिकरण द्वारा कॉपर कन्सन्ट्रेट तथा कोयले के लिए लागू की गई 'परिमाण छूट योजना' के पुनरीक्षण के लिए टीपीटी ने एक याचिका दर्ज की है। टीपीटी ने अपनी याचिका में निम्न विदुओं को प्रस्तुत किया है :-

- (i) सामान्य संशोधन क्रम के रूप में परिमाण छूट योजना को शुरू किए जाने के लिए पत्तन या उपयोक्ताओं की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं था। एसआईएल ने कॉपर कन्सन्ट्रेट को 'अयस्क तथा खनिज' श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाने का अनुरोध किया था, जेटटी पर संचालित होने वाले कोयले तथा कोक के संबंध में परिमाण छूट के लिए किसी भी उपयोक्ता की ओर से कोई अभ्यावेदन नहीं था।
- (ii) उक्त उपयोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले यातायात के संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित परिमाण छूट योजना यथार्थपरक नहीं है। संबंधित उपयोक्ताओं द्वारा विगत 3 वर्षों में परिचालित यातायात निम्नवत है :-

(लाख टन में)

वर्ष	कॉपर कन्सन्ट्रेट	कोयला जेटटी संचालित कोयला तथा कोक
1999-2000	3.50	35.54
2000-2001	4.03	56.58
2001-2002	5.42	51.95

- (iii) यह उल्लेख किया गया है कि यद्यपि आधार दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी परिमाण छूट योजना को संचालित होने वाले वर्तमान वार्षिक यातायात का 50% है। संबंधित उपयोक्ताओं द्वारा परिचालित किए जाने वाले वर्तमान वार्षिक यातायात का 50% परिमाण छूट योजना की परिकल्पना हेतु उचित नहीं है।

- (iv) परिमाण छूट किसी वर्ष विशेष के दौरान हुए परिमाण वृद्धि या विगत तीन वर्षों के दौरान संचालित उच्चतम परिमाण पर ही दी जानी चाहिए।
- (v) यदि प्राधिकरण ने टीपीटी को परिमाण छूट योजना शुरू करने के लिए टीपीटी को सलाह दी होती तो पत्तन के पास पत्तन तथा उपयोक्ताओं की पारस्परिक सहमति से जुड़े उचित प्रस्ताव होते। यदि प्राधिकरण ने इससे पत्तनों को भी ऐसी सलाह नहीं दी है तो यह सलाह भी बहुत उचित नहीं होगी।
- (vi) जहां दूसरे पत्तनों (जैसे मुरगांव पत्तन) को उनके बेहतर उत्पादकता के लिए प्रस्तुत किया गया है वही तूतीकोरिन पत्तन को अपने उत्पादकता स्तर में बढ़ोत्तरी के बावजूद दंडित किया गया है।
- (vii) उपरोक्त बिंदुओं के महेनजर प्राधिकरण से कोयला जेटी पर हैंडल किए जाने वाले कोक, कोयला तथा कॉपर कन्सन्ट्रेट के लिए निर्धारित स्लाइडिंग दरों की समीक्षा तथा सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात अख्यापक आदेश दिए जाने का अनुरोध किया जाता है।

4.2 टीपीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि चूंकि एसपीआईसी द्वारा संचालित यातायात अनिश्चित रहा है तथा उसके द्वारा संचालित माल के परिमाण में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। एसपीआईसी संचालित माल के लिए परिमाण छूट योजना शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान आय-व्यय संबंधी आँकड़ों तथा वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए संपूर्ण आंकलित यातायात हेतु आय के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात प्रशुल्क को वर्तमान स्तर पर रखने या वर्तमान प्रशुल्क को वारंटीनुसार बढ़ाने/घटाने के बारे में शीघ्र ही विस्तृत गणना प्रस्तुत करने के लिए भी सहमत हुआ है।

5.1 प्रस्ताव की प्रति विभिन्न संबंधित उपयोक्ताओं/पत्तन उपयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकायों के पास टिप्पणी हेतु भेजी गई थी। उनसे प्राप्त टिप्पणी प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में टीपीटी को भेज दी गई थी।

5.2 इस मामले पर दिनांक 5-2-2003 को टीपीटी परिसर में संयुक्त सुनवाई हुई। इस सुनवाई में टीपीटी तथा पत्तन उपयोक्ताओं ने अपने निवेदन प्रस्तुत किए।

5.3 इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाही प्राधिकरण के कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों के उद्धरण तथा संबंधित पार्टियों द्वारा किए गए तर्क अलग से संबंधित पार्टियों के पास भेजे जाएंगे। ये व्योरे हमारी वेबसाइट (www.tamp.nic.in) पर भी उपलब्ध होंगे।

6. मामले की कार्यवाही के दौरान संग्रहीत सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :-

- (i) टीपीटी के प्रशुल्कों की पिछली सामान्य संशोधन कार्यवाही में उसके वित्तीय/लागत स्थिति की संवीक्षा से राजस्व अधिशेष की स्थिति सामने आयी है। तथापि, प्राधिकरण ने पाया कि प्रशुल्क में स्वाभाविक कटौती प्रभाव होने के बजाय शुल्क में कमी संबंधी प्रस्ताव के लिए टीपीटी को छह माह का समय दिया जाना तर्क संगत होगा। इस निर्णय के बावजूद, प्राधिकरण ने कॉपर कन्सन्ट्रेट तथा कोयले के लिए इस तथ्य को दृष्टिगत रखकर कि टीपीटी के माल यातायात में इन दोनों मालों की प्रमुख हिस्सेदारी है परिमाण छूट योजना लागू करने का निर्णय लिया।
- (ii) टीपीटी का आरोप है कि शुरू की गई योजना उपयोक्ताओं के बीच भेदभाव करती है तथा यह रवैया पत्तनों के बीच भी भेदभावपूर्ण है। इस प्राधिकरण ने विभिन्न पत्तनों के प्रशुल्क निर्धारण संबंधी अवधारणाओं तथा सिद्धान्तों की समानता की हमेशा वकालत की है। परिमाण छूट योजना जैसी धारणा केवल टीपीटी से ही नहीं जुड़ी है। इस प्राधिकरण ने (स्वप्रेरणा से भी) अन्य प्रमुख पत्तनों के लिए भी परिमाण छूट योजना शुरू की है। ऐसी स्थिति में, प्राधिकरण द्वारा पत्तनों के बीच भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उसी तरह प्राधिकरण उपयोक्ता उन्मुखीकरण पर बल देता है इसलिए इस पर उपयोक्ताओं के बीच भेदभाव करने के आरोप का कोई तर्क नहीं है। जैसा कि यह एआईसीसीआई ने यह सही बात कही है कि कोयला तथा कॉपर कन्सन्ट्रेट टीपीटी के प्रमुख सामग्रियों में से है, इसलिए इन सामग्रियों के लिए परिमाण छूट पहले घरण में लागू किए गए, जबकि अन्य कारणों के लिए प्रशुल्क कमी संबंधी टीपीटी का प्रस्ताव लंबित था।

(iii) टीपीटी ने यह भी उल्लेख किया है कि प्राधिकरण ने अपने प्रस्ताव के साथ स्टरलाइट द्वारा दाखिल अभ्यावेदन को भी सम्मिलित कर लिया है। इस संबंध में सरकार द्वारा दिए गए नीति संबंधी निदेश कि प्राधिकरण व्यक्तिगत उपयोक्ता का अभ्यावेदन स्वीकार न करे, कै मदेनजर स्टर्लिंट द्वारा दाखिल अभ्यावेदन संबंधी मामला बंद कर दिया गया है। तथापि पत्तन न्यासों द्वारा दाखिल प्रशुल्क संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पूर्व, सरकार के निदेश प्राधिकरण को सामान्य परामर्श प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकते हैं। टीपीटी के प्रशुल्क संबंधी पिछले सामान्य संशोधन कार्यवाही के दौरान कच्ची सामग्रियों पर परिमाण छूट शुरू किए जाने की स्टरलाइट की एक विशिष्ट मांग थी, जो टीपीटी द्वारा गेहूँ के लिए प्रस्तावित परिमाण छूट की तर्ज पर थी। ऐसी स्थिति में, यह कहना ठीक नहीं है कि कॉपर कन्सन्ट्रेट के लिए परिमाण छूट का शुरू किया जाना स्टरलाइट द्वारा किसी अन्य मामले में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर आधारित है। इसलिए यह स्पष्ट है कि कॉपर कन्सन्ट्रेट पर परिमाण छूट शुरू किए जाने का निर्णय व्यक्तिगत उपयोक्ता के संबंध में सरकार द्वारा जारी नीति संबंधी निदेश का उल्लंघन नहीं करता।

(iv) टीपीटी ने यह भी उल्लेख किया है कि परिमाण छूट योजना के शुरू किए जाने से पूर्व उससे सलाह नहीं ली गई। परिमाण छूट योजना संबंधी मुद्दे पर विद्यार 6 जून, 2002 की संयुक्त सुनवाई में किया गया जबकि टीपीटी ने ऐसी योजना के विरुद्ध राय व्यक्त की थी। तथापि यह स्वीकार किया जाता है कि संयुक्त सुनवाई में परिमाण छूट के सिद्धांत पर चर्चा की गई, न कि कॉपर कन्सन्ट्रेट तथा कोयले पर शुरू की गई परिमाण छूट योजना के सही व्योरों पर।

(v) टीपीटी ने यह उल्लेख किया है कि योजना में निर्धारित किए गए परिमाण (लक्ष्य) संबद्ध उपयोक्ताओं द्वारा काफी पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं। इसलिए यह योजना अतिरिक्त परिमाण को लुभाने में कारगर नहीं हो सकेगी। जैसाकि पहले स्वीकारा जा चुका है कि योजना में प्रयुक्त मानक तदर्थ है तथा यह यातायात के पैटर्न तथा वृद्धि के सावधानीपूर्वक किए गए विश्लेषण पर आधारित नहीं है। यह योजना पत्तन के दो प्रमुख उपयोक्ताओं को राहें देने की मंशा से शुरू की गई है। उस अर्थ में, यह योजना वास्तव में अतिरिक्त यातायात आकर्षित करने वाली परिमाण छूट योजना न होकर इन कारणों के लिए अपेक्षाकृत एक क्रमवार घाटशुल्क अनुसूची है।

इस प्राधिकरण ने विद्यमान दरों में कटौती के लिए टीपीटी को पहले ही छह माह का समय दे दिया है। टीपीटी ने दिनांक 4 अप्रैल, 2003 तक की समयावधि में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। इसने यह भी आश्वासन दिया है कि वहकॉपर कन्सन्ट्रेट तथा कोयले के दर सहित सभी कारणों के लिए परिमाण छूट योजना शुरू करने पर विशेष विद्यार करेगा। चूंकि शुरू की गई परिमाण छूट योजना तदर्थ मानकों पर आधारित है तथा टीपीटी ने विश्लेषण आधारित प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया है तो प्राधिकरण के दिनांक 20 सितंबर, 2002 के आदेश द्वारा शुरू की गई परिमाण छूट योजना को 31 मार्च, 2003 तक प्रभावी रखा जाना संगत है। चूंकि दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से परिमाण छूट योजना लागू नहीं रहेगी, तदोपरांत कोयले तथा कॉपर कन्सन्ट्रेट पर संशोधन पूर्व घाटशुल्क देय होंगे।

इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि एसपीआईसी तथा टीएनईबी ने भी यह स्वीकार किया है कि उनकी मामला संबंधी अङ्गचनों के चलते परिमाण में वृद्धि नहीं हो सकती है। यह भी टीपीटी के परिमाण छूट योजना तथा यातायात वृद्धि संबंधी तर्क को और मजबूती प्रदान करता है।

(vi) योजना के लागू किए जाने के संदर्भ में, उपरोक्त परिच्छेद 3.2 में सविस्तार स्पष्टीकरण पहले ही दिया गया था। टीपीटी का अनुरोध है कि सामान्यतया इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू न किए जाएं। दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार दर भूतलक्षी प्रभाव से कम नहीं की गई हैं। स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जा चुका है कि (तथाकथित) आदेश के कार्यान्वयन की तिथि से प्रचालित होने वाले केवल कारगों ही घाटशुल्क दर में छूट के योग्य होंगे। कारगों के परिमाण को मापने के लिए एक सुदारु वित्तीय वर्ष आधार मानने की दृष्टि से यह स्पष्टीकरण दिया गया है। इस प्राधिकरण द्वारा परिमाण छूट योजना को केवल दिनांक 31 मार्च, 2003 तक लागू रखे जाने की दशा में वित्तीय वर्ष आधारित परिमाण ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। इसलिए प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि योजना के कार्यान्वयन की वास्तविक तिथि से 31 मार्च, 2003 तक की अवधि के दौरान अनुपाततः परिमाण आधार पर कॉपर कन्सन्ट्रेट तथा कोयले के घाटशुल्क में छूट दी जाए, जो पहले दिए गए स्पष्टीकरण के अधिक्रमण में होगी।

7. परिणामस्वरूप तथा उपर्युक्त कारणों से और समग्र विद्यार-विमर्श के आधार पर प्राधिकरण निम्नानुसार निर्णय लेता है :-

- (i) दिनांक 20 सितंबर, 2002 के पूर्व आदेश के द्वारा कॉपर कन्सन्ट्रेट तथा थर्मल कोल के लिए शुरू की गई परिमाण छूट योजना की समीक्षा संबंधी टीपीटी के तर्क में कुछ बल है।
- (ii) कॉपर कन्सन्ट्रेट तथा कोयले के लिए विद्यमान परिमाण छूट योजना 31 मार्च, 2003 तक प्रभावी रहेगी।
- (iii) 31 मार्च, 2003 तक योजना के नियमन के लिए योजना के कार्यान्वयन की वास्तविक तिथि से संचालित यथानुपात परिमाण का हिसाब रखा जाए।

अ. ल. बोगिरवार, अध्यक्ष
[सं. विज्ञापन/III/IV/143/02-असाधारण]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION**

Mumbai, the 26th March, 2003

No. TAMP/7/2003-TPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal from the Tuticorin Port Trust (TPT) for review of the volume discount scheme on copper concentrate and coal as in the Order appended hereto.

Case No. TAMP/7/2003 - TPT

The Tuticorin Port Trust

Applicant

ORDER

(Passed on this 17th day of March 2003)

This case relates to a proposal received from the Tuticorin Port Trust (TPT) for review of the volume discount schemes introduced for copper concentrate and coal.

2.1. This Authority had passed an Order on 20 September 2002 in the general revision case of the TPT. This Authority for the reasons stated in that Order, held that the classification of Copper Concentrate under the specific entry was in order; and, therefore, the wharfage rate for the specific item of Copper Concentrate was not changed. Nevertheless, in view of the volume of traffic of copper concentrate and in view of financial surplus position reflected in the cost statement, a volume discount scheme was prescribed for this item keeping the base rate at the existing level. Likewise, a volume discount scheme for coal was also introduced without disturbing the basic wharfage rate bearing in mind the fact that coal is a major commodity handled at the TPT.

2.2. Since the SPIC, another major user of the TPT, had not suggested anything concrete with supporting details, the TPT and the SPIC were advised to examine the issue of introducing volume discounts and, to come up, preferably, with an agreed proposal.

3.1. M/s. Sterlite Industries Limited (SIL) have sought clarification about the date of application of the volume discount scheme as to whether the date per annum means financial year of the port i.e. 1 April to 31 March 2001 and if so whether the volume discount is applicable for the current financial year.

3.2. In this regard, it has been clarified that the quantity of copper concentrate handled from 1 April 2002 till the effective date of implementation of the volume discount scheme i.e. 20 October 2002 will be liable to pay wharfage charges as per the pre-revised Scale of Rates; only the quantity of copper concentrate handled from the date of implementation of the scheme upto 31 March 2003 will be eligible for the rebate in wharfage rate insofar as the financial year 2002-03 is concerned. It has also been pointed out that the quantity of cargo handled since 1 April 2002 will be reckoned with to determine the appropriate slab of wharfage rate payable from the date of implementation of the volume discount scheme.

3.3. In response to our clarification, the TPT has pointed out that the volume discount scheme in its entirety can be effective only from 19 October 2002; and, the terminology per annum means a running year from the date of implementation of the Order. In this back drop, it has requested this Authority to review the clarification offered; and, approve the implementation of the volume discount schemes with effect from 19 October 2002 to 18 October of the each following year pending a decision on its review petition.

4.1. The TPT has also filed a petition for review of the volume discount scheme introduced by this Authority for copper concentrate and coal. The TPT has made the following main points in its review petition:

- (i). There was no proposal from the port or the users for introduction of volume discount scheme as a part of general revision exercise. The SIL had requested for classification of copper concentrate under 'Ores and Mineral'; in respect of coal and coke handled at the jetty there was no representation from any user for volume discount.

(ii). The volume discount scheme prescribed by the Authority is not realistic with respect to the traffic handled by the said users. The traffic handled by the concerned users for the past three years are as follows:

Year	Copper Concentrate	Coal and coke handled through coal jetty.	(in lakh tonnes)
1999-2000	3.50	35.54	
2000-2001	4.03	56.58	
2001-2002	5.42	51.95	

(iii). It has pointed out that though the base rate is not altered, the volume chosen for introduction of volume discount scheme is 50% of the current annual traffic handled. It is not appropriate to pick up 50% of the current year traffic handled by the respective users while envisaging the volume discount scheme.

(iv). Volume discount should be offered on the incremental volume during a particular year or over the highest volume handled in the past three years.

(v). If the Authority had advised the TPT to introduce a volume discount scheme, the port would have come out with a suitable proposal which is mutually agreeable to the port and the users. Such an advice would also not be very appropriate if similar advice has not been rendered by the Authority to the other Ports as well.

(vi). While other ports (like the Mormugao Port) have been rewarded for showing better productivity, the Tuticorin port has been penalised despite improving its productivity levels.

(vii). In view of the above points, the Authority is requested to review the sliding rates prescribed for copper concentrate and coal and coke handled at the coal jetty and issue a speaking order after giving an opportunity of hearing.

4.2 The TPT has further clarified that since the traffic handled by the SPIC has been volatile and as there is no increase in the volume of cargo handled by the SPIC, volume discount scheme need not be introduced for the cargo handled by the SPIC. It has also agreed to submit shortly a detailed calculation about keeping the tariffs at existing level or to increase/decrease the existing tariff wherever warranted after considering the current income and expenditure figures, impact of income tax for traffic throughput estimated for the years 2002-03 and 2003-04.

5.1. A copy of the proposal was forwarded to various concerned users/representative bodies of port users for comments. The comments received from the various users/representative bodies of port users were forwarded to the TPT as feed back information.

5.2. A joint hearing in this case was held on 5 February 2003 at the TPT premises. At the joint hearing, the TPT and the port users have made their submissions.

5.3 The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpts of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be available in our website (www.tamp.nic.in).

6. With reference to the totality of information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i). Scrutiny of the financial / cost position of the TPT as a part of the proceeding relating to the last general revision of tariffs at the TPT revealed a revenue surplus position. This Authority, however, found that it would be reasonable to allow the TPT a six months' time to propose reduction in tariff instead of effecting a *suo motu* reduction. Notwithstanding this decision, volume discount schemes for Copper Concentrate and coal were introduced bearing in mind the fact that the traffic of these two commodities form major share at the TPT.

(ii). The TPT has now alleged that the scheme introduced discriminates users and the approach adopted discriminates between ports. This Authority has always advocated for uniformity in the concepts and principles applied for tariff setting across different ports. The concept of volume discount scheme is not perceived only in the concept of the TPT. This Authority has introduced (even *suo motu*) volume discount schemes at other major ports also. That being so, the question of this Authority discriminating between ports does not arise at all.

Likewise, there is no reason why this Authority which stresses on user orientation should discriminate between users. As has been correctly pointed out by the AICCI, coal and copper concentrate are the major commodities handled at the TPT; and, therefore, volume discounts for them were introduced in the first instance pending the TPT proposing a reduction in tariff for other cargo.

(iii). The TPT has also pointed out that this Authority has clubbed its proposal with an individual representation filed by the Sterlite. In view of the policy direction given by the Government about this Authority not entertaining representations from individual users, the case relating to the representation filed by the Sterlite was closed. The direction issued by the Government, however, does not restrain this Authority to follow the usual consultation process before deciding the tariff proposals filed by the port trusts. In the proceeding relating to the last general revision of tariff at the TPT, there was a specific demand from the Sterlite for introduction of volume discounts for raw materials in line with the volume discounts proposed by the TPT to be allowed on wheat. That being so, it is not correct to say that the introduction of volume discounts for copper concentrate is based on a representation filed by the Sterlite in some other case. It is, therefore, clear that the decision to introduce volume discounts for copper concentrate does not violate the policy direction issued by the Govt about individual users.

(iv). The TPT has also pointed out that it was not consulted before the volume discount scheme was introduced. The issue relating to volume discount scheme was considered at the joint hearing held on 6 June 2002 when the TPT expressed its view against such schemes. It is, however, to be admitted that the discussion at the joint hearing was on the principle of volume discounts and not on the exact details of the volume discount schemes introduced for copper concentrate and coal.

(v). The TPT has now pointed out that the volumes prescribed in the schemes have been achieved by the concerned users long ago and, therefore, the schemes may not be useful in attracting additional volumes. As has been admitted earlier, the parameters used in the schemes are ad hoc and not based on any careful analysis of the traffic pattern and growth. The schemes have been introduced with the intention of providing relief to the two major users of the port. In that sense, the scheme is not really a volume discount scheme with the objective of attracting additional traffic but more of a graded wharfage schedule for these cargo.

This Authority has already allowed six months' time to the TPT to propose reduction in the existing rates. The TPT has assured that it will come up with a proposal within the stipulated time limit allowed upto 4 April 2003. It has also made an assurance that it will specially consider introducing volume discount schemes for all cargo including the rates for copper concentrate and coal. Since the volume discount scheme introduced is based on ad hoc parameters and the TPT has assured to come up with a well analysed proposal, it is found reasonable to allow the volume discount schemes introduced vide this Authority's Order dated 20 September 2002 to operate till 31 March 2003. Since the volume discount schemes will not be in operational from 1 April 2003, the pre-revised wharfage rates will apply to coal and copper concentrate thereafter.

In this context, it is noteworthy that the SPIC and TNEB have also admitted that their volumes may not go up due to capacity constraints. This also bolsters the TPT argument relating to volume discount scheme and traffic growth.

(vi). With reference to the applicability of the scheme, a clarification was earlier issued as detailed in paragraph 3.2 above. The TPT has requested that no retrospective effect should generally be given to the Order passed by this Authority. The clarification given does not reduce the rates retrospectively. It has been categorically mentioned that only the cargo handled from the date of implementation of the impugned Order will be eligible for the rebate in wharfage rate. This clarification has been given with an idea to adopt a convenient financial year basis for measuring the volume of cargo. With the decision to allow the volume discount schemes to operate only upto 31 March 2003, the issue relating to financial year-wise volumes has lost its relevance. The rebate in wharfage for copper concentrate and coal should, therefore, be allowed by taking pro-rata volumes for the period from the original date of implementation of the scheme upto 31 March 2003 in supersession of the clarification earlier given.

7. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority decides as follows:

- (i). The argument of the TPT for a review of the volume discount schemes for copper concentrate and thermal coal introduced vide earlier Order dated 20 September 2002 carries some force.
- (ii). The existing volume discount schemes for copper concentrate and coal will operate upto 31 March 2003.
- (iii). For regulating the scheme upto 31 March 2003, pro-rata volume handled from the original date of implementation of the scheme should be reckoned with.

A. L. BONGIRWAR, Chairman
[No. ADVT/III/IV/143/02-Exty.]